योजना नहीं बनाती, तब तक यह विभी-षिका और अधिक भीषण होती जाएगी और भारत की प्रतिष्ठा कम होती जाएगी।

सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह समाज के इस वर्ग को, जोकि भिक्षावृत्ति में लगे हैं तथा पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सम्माननीय जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने में तथा आगामी पीढ़ियों को इस विभीषिका से बचाने के लिए उपाय करे और इस संबंध में कानून भी बनाए।

MR. DEPUTY SPEAKER : Hon. Members, we go to the next item, Items 11 & 12. The time alloted is two hrs. We have already spent more than one and a half hours. There are about two or three speakers, two from the opposition and one from the ruling party. I would request each Hon. Member not take more than three to four minutes. We have got to complete the Bill by 3-30. Now, I call Shrimati Pramila Dandavate.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : This is second reading.

MR. DEPUTY SPEAKER : I know you will all co-operate. I know. Mr. Ramavatar Shastri is my friend, always.

CINE-WORKERS WELFARE CESS BILL

AND

CINE-WORKERS WELFARE FUND BILL (*Contd.*)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वसंत साठे जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। रोज-रोज हमारी ओर से आलोचना सुनते हैं, हमें करनी पड़ती है—आज इन्होंने धन्यवाद देने का मौका दिया है। सौ फीसदी धन्यवाद तो नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी यह जो प्रयास है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक करोड़, 25 लाख लोग रोजाना पिक्चर देखते हैं। इतना प्रभावशाली माध्यम है। अगर सरकार चाहती तो इसके जरिए समाज में पूरा परिवर्तन कर सकती थी।

जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, एक नया समाज बनाना चाहते हैं, शोषण विहीन समाज बनाना चाहते हैं और उसके अनुरूप लोक धारणा, मानसिक धारणा बनाना चाहते हैं तो उसके लिऐ फिल्में सर्वोत्तम माध्यम सिद्ध हो सकती हैं। कोई और इतना अधिक प्रभावशाली माध्यम इसके लिए आपको नहीं मिल सकता है सिवाय फिल्मों के। नेशनल इंटीग्रेशन लाने में भी फिल्में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। हम देखते हैं कि दक्षिण के लोगों में जहां हिन्दी का विरोध हुआ करता था वहां पर आज हिन्दी पिक्चर्ज बहुत पापुलर हो रही हैं। हिन्दी पिक्चर्ज की कापियां भी वहां बनने लगी हैं। इसका साफ मतलब है कि फिल्में विहीकल फार नेशनल इंटीग्रेशन भी हो सकती हैं। इस माध्यम के बारे में इतने सालों के बाद जो आप सोचने का काम कर रहे हैं यह अच्छा काम है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

हमारे देश में सुन्दर-सुन्दर पिक्चर्ज भी बनती हैं और गन्दी भी बनती हैं। कहा जाता है कि समाज में जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसके लिए भी फिल्म इन्डस्ट्री बहुत हद तक जिम्मेदार है। ऐसा सोशल थिंकर्ज का विचार है और दूसरे लोगों का भी विचार

[श्रीमती प्रमिला दण्डवते]

है। साथ ही इस क्षेत्र में एक्सप्लायटेशन भी बहुत भारी होता है। कोई-कोई तो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 32-32 लाख रुपया एक पिक्चर का लेते हैं। फिल्म इण्डस्ट्री में मेरी भी दिलचस्पी है। मैं फिल्में देखती हूँ, मैग्जीन पढ़ती हूं। मैंने पढ़ा है कि 32-32 लाख रुपया एक एक आर्टिस्ट एक एक पिक्चर का लेता है। दो तीन या छः सात लाख लेना तो मामूली बात हैं। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब उनके पास कुछ नहीं रहता। जो आर्टिस्ट व्यवहारिक रूप से जिन्दगी नहीं बिताते ऐसा भी देखने में आया है कि आगे चल कर वे पापर बन जाते है। लेकिन आज फिल्म इण्डस्ट्री में बहुत होशियार लोग भी बन गए हैं। उन्होंने इनवैस्टमेंट पैसे का करना शुरू कर दिया हैं। उन्होंने इण्डस्ट्री, कारखाने आदि भी चलाने शुरू कर दिए हैं। इटली आदि में उन्होंने अपने होटल भी खोल रखे हैं। आज उनकी हालत इतनी खराब नहीं है। अगर किसी की हालत फिल्म इन्डस्ट्री में खराब है तो वह टैक्नीशियज की है, एक्ट्राज़ की है। उनके बारे में मंत्री महोदय को सोचना चाहिये।

मंत्री महोदय ने एक पिक्चर पर एक प्रोडयूसर से एक हजार रुपया लेने की बात कही है। मैं समझती हूं कि यह बहुत कम है। एंटरटेनमेंट टैक्स न लगता हो तो यह भी न लेने की शायद बात उन्होंने कही है। मैं नहीं समझती हूं कि इस तरह के कंसेशन देने की कोई जरूरत है। सर्टिफिकेट देते समय एक हजार फी लेने की व्यवस्था की गई है। इससे इनमें काम करने वालों को जरूरत पड़ने पर राहत पहुँचाई जाएगी। जो लोग इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं उनके भविष्य के बारे में हमें कुछ निर्णय करना चाहिये। मुझे तो लगता है Our Minister should come forward with a Bill for insurance for the artists. जब वे इतना पैसा कमाते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा इन्शोरेंस के लिए भी उनसे लिया जाना चाहिये ताकि जब उनके पास कोई काम न हो तो उस पैसे से उनके वैलफेयर की व्यवस्था की जा सके।

मैं यह भी समझती हूं कि जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं उनसे भी अलग से पैसा लिया जाना चाहिये। जो बड़े ऐश और आराम में रहते हैं, चमक दमक के साथ रहते हैं उनको अपने ही क्षेत्र में रहने और काम करने वाले गरीब आर्टिस्टों के वास्ते कुछ न कुछ करना चाहिये, जिनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है उनके लिए कुछ करना चाहिये। यह उनका कर्त्तव्य भी है। काला या सफेद जो भी धन उनको मिलता है उसमें से एक परसेंट उन से सरकार को लेना चाहिये।

Film industry is a den of sexual exploitation.

एक्सट्राज और एक्ट्रेसिस के बारे में हम तरह-तरह की कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं। इनको पढ़ सुन कर हमें दुख होता है। इनका जो एक्सप्लायटेशन होता है इसको रोका जाना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The film itself is black and white !

श्रीमती प्रमिला दंडवते : हमें पता नहीं है, जो हम पढ़ते हैं वह बता रहे हैं। उनके लिए भी कुछ करना चाहिये। जो वैलफेयर मैयर्ज आप ले रहे हैं उसमें इस एक्सप्लायटेशन को रोकने की भी आपको कोशिश करनी चाहिये। एक्सट्राज की हालत आज बहुत खराब है। जगह-जगह पर स्टूडियोज के बाहर महिलाएं बैठी रहती हैं खुशामद करती रहती हैं और कुछ भी करने के लिए वे मजबूर होती हैं। उनके एक्सप्लायटेशन

को खत्म करने के लिए वैलफेयर मैयर्ज जो है उनमें इसको भी स्थान मिलना चाहिये।

आप कहते हैं कि साढ़े सात लाख एकत्र होगा। यह बहुत कम है। जिनके लिए आप इस पैसे को खर्च करने वाले हैं उनके लिए इससे कुछ नहीं होगा। कैसे आप इसको खर्च करने वाले हैं इसके बारे में भी आपने कुछ नहीं कहा है। आपने यही कहा है Only the advisory committee will perhaps decide. घर देंगे, तनख्वाह देंगे, कैसे आप खर्च करेंगे आपने कुछ नहीं बताया है। हमारी फिल्म इन्डस्ट्री का दुनिया में आज भी दूसरा नम्बर है। आपको देखना चाहिये कि इस पैसे को कैसे दुगुना और तिगुना किया जा सकता है। जैसे मैंने सुझाव रखे हैं वैसे आप करें तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। मेरा कहना है कि Film industry should be treated at par with other industries. It is one of the biggest industries and the biggest source of exploitation in our country. अगर यह हमें करना है तो मेरी प्रार्थना है कि जितने लोग उसमें काम करते हैं उनका रजिस्टर होना चाहिये, कितना उनको पैसा दिया जाता है उसका रजिस्टर होना चाहिये। ऐसा अगर करेंगे तो जो उनकी बाकी सुविधायें हैं वह हम इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट और लेबर ऐक्ट के अन्दर देने की कोशिश कर सकते हैं। माननीय साठे जी एक जमाने में ट्रेड यूनियन लीडर थे इसलिये वर्कर्स के लिये खास कर जिनको कम पैसा मिलता है उनके प्रति उन्हें हमदर्दी होना स्वाभाविक है। आपने जो बिल रखा है वह पहला कदम है, लेकिन अधूरा है उसको पूरा करने के लिये कम्प्रीहेंसिव कानून बनाने की जरूरत है। मुझे पता है कि फिल्म इन्डस्ट्री के लोग बहुत प्रैशर डाल रहे हैं यह कह कर हमारी इन्डस्ट्री मर जायगी। लेकिन उससे ज्यादा प्रैशर इस देश के गरीब लोग आप पर डालेंगे कि इस इन्डस्ट्री को एक इन्डस्ट्री बना दीजिये ताकि वहां काम करने वाले लोगों को सुरक्षा मिल सके। आपने जो सोशल वेलफेयर फण्ड बनाया है यह अच्छा है, लेकिन इसकी रकम को बढ़ाना चाहिये। और इस अधूरे कानून को पूरा कानून बनाने का आप प्रयास करें, यही मेरा निवेदन है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, हमारे सुयोग्य सूचना मन्त्री जी ने जो सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक पेश किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। विरोधी पार्टी के एक सज्जन ने शुरुवात करते हुए एक बात कही कि यह विधेयक मजदूर विरोधी है और दूसरी बात की कि राज्य के अधिकारियों के विरुद्ध है। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को चमन में हरियाली होते हुए भी नजर नहीं आती। तो देखने वाले का दोष है, दोष चमन का नहीं है। कल्याण की योजना से बनाया गया यह विधेयक है। यह हकीकत है कि इस सिनेमा क्षेत्र के अन्दर बड़े-बड़े कलाकार अपने युग में कई ऐसे देखे जो उच्च स्थान पर थे, परन्तु बढ़ापा आते ही उनकी बड़ी दयनीय स्थिति रही। डागा जी ने कल एक बात कही कि फिल्म कलाकार और राजनीतिक नेता जितने बूढ़े होते हैं, उन्होंने रंगा जी का नाम लिया, उन पर रौनक आती है। पर डागा जी ने सेन्ट्रल हाल में नहीं देखा कि जो मेम्बर नहीं रहे या मन्त्री नहीं रहे उनके चेहरों की क्या हालत है। वहां जो कलाकार हैं उनके चेहरे उन्होंने नहीं देखे। यह हकीकत है कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। श्रीमती

[आचार्य भगवान देव (अजमेर)]

दंडवते ने एक बात कही कि आजकल के कलाकारों ने अपने पैसे का अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पर उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस बिल का सम्बन्ध बड़े-बड़े लोगों से नहीं है, बल्कि जो गरीब हैं और जिनकी स्थिति दयनीय है या हो गई है उनके लिए यह बिल है। यह हकीकत है कि यदि सिनेमा उद्योग को एक उद्योग घोषित किया जाता और उनकी सुविधायें मिल जातीं तो यह बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह लाया ही इसी लिए गया है कि उद्योग अभी तक घोषित नहीं हुआ है और कई कलाकार ऐसी गरीब हालत में हैं कि वह खाने के लिए मोहताज हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात तो दूर रही। हमें आशा है कि जो कलाकार रहे हैं मन्त्री जी उनका अवश्य कल्याण करेंगे।

कई शंकायें खड़ी की गई कौन-सी कमेटी होगी, कैसी कमेटी होगी, उसके आफिस पर इतना खर्च होगा। हमेशा कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो उसकी रूप-रेखा तैयार होती है। उपाध्यक्ष जी, सिनेमा क्षेत्र के अन्दर कुछ मित्र लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, अनेक लोग जो जीवन के उतार और चढ़ाव से गुजरे हुए हैं। ऐसे बहुत से बड़े कलाकार हैं फिल्म इन्डस्ट्री में। स्वर्गीय नरगिस दत्त के बारे में भी आप जानते होंगे उन्होंने भी एक संगठन खड़ा किया कल्याण की दृष्टि से, अशोक कुमार भी अपनी तरफ से मदद करने के कुछ प्रयास करते हैं, राजकपूर और प्राण भी करते हैं। जो पुराने व्यक्ति हैं, जिन्होंने जीवन में उतार-चढ़ाव देखें हैं, वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करते हैं लेकिन सामूहिक रूप से कोई प्रयास नहीं किया गया। यह प्रयास हमारे माननीय मंत्री महोदय ने किया है, जो कि बहुत सुन्दर है।

परम आदरणीय श्री कमलापति जी कह रहे थे, जिस दिन शुरुआत हुई, कि न सिर्फ फिल्म क्षेत्र में काम करने वालों के बारे में सोचें, जैसे रंगा जी ने भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नाटक दिखाते हैं, या रास लीला, कृष्ण लीला या रामलीला करने वाले जो कलाकार हैं उनके बारे में भी ध्यान रखें। परन्तु उसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके बारे में भी अगर मंत्री जी कोई योजना बनायें तो बहुत अच्छा है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आपके आकाशवाणी के केन्द्रों में आकर अपनी जवानी के टाइम में बहुत सुन्दर-सुन्दर गीत गुनगुनाकर जनता का जन-मनोरंजन करते रहे हैं। बंसी-वादक भी रहे हैं जो अपनी जवानी में बहुत सुन्दर बंसी बजाते थे लेकिन बुढ़ापा आने पर उन लोगों को पान-बीड़ी बेचते हुए देखा गया है। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिनका आपके आकाशवाणी से सम्बन्ध रहा है, जिस विभाग के आप मंत्री हैं, मेरा निवेदन है कि उनके बारे में भी आप विचार कीजिये। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति बन चुकी है, आप देखें कि वे कौन-कौन हैं, उनके बारे में भी योजना बनाइये। ऐसे बहुत कम केसेज़ मिलेंगे जो कि अब भी जीवित हैं जिन्होंने अपने टाइम में बहुत सुन्दर गाया है अच्छे संगीत पेश किये हैं और मनोरंजन पेश किया है। परन्तु उनका बुढ़ापा आते ही न उनके स्वर में ताकत रही और न शरीर में दम रहा, वह न नाटक पेश कर सकते हैं न सुन्दर गा सकते हैं। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। उनका भी सम्मान किया जाना चाहिये। उनकी कठिनाइयों को भी दूर

करने की आवश्यकता है। न सिर्फ कलाकार की तरफ ध्यान देने की जरूरत है बल्कि कलाकार के परिवार और उनके बच्चों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री जी जो विधेयक ला रहे हैं, उसमें जो कल्याण की योजना बना रहे हैं उसमें उनके बच्चों को सुविधा देने के प्रयास हो सकें तो अच्छा है। फिल्म लाइन के लोगों के लिये जो आप कमेटी बना रहे हैं उसमें जो व्यक्ति लिये गये हैं वह स्वागत योग्य हैं। उसमें सरकार के भी सुयोग्य व्यक्ति हैं। डागा जी ने तो मंत्री जी को सर्टिफिकेट दे दिया कि फिल्म लाइन की पत्रिका का उन्हें अच्छा ज्ञान है मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा किये गये प्रयासों से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी।

मैं आशा करता हूं कि जो कलाकार रह चुके हैं, उनके लिये, उनके परिवारों के लिये और बच्चों के लिये मंत्री महोदय पूरा ध्यान रखेंगे लेकिन उसके साथ-साथ रेडियो स्टेशनों के साथ जिन कलाकारों का सम्बन्ध रहा है जिन्होंने वहां अपना जीवन लगा दिया है उनके सम्बन्ध में भी कोई ठोस योजना रखेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं हृदय से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह बहुत ही सुन्दर और अपने आप में पूर्ण विधेयक है। अभी तक इस उद्योग को औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किया है किन्तु यह अच्छा प्रयास है। रासलीला, रामलीला करने वालों के बारे में भी कोई प्रयास हो और इस कमेटी को इस तरह से आदेश दे सकें जिससे कलाकारों का सम्मान हो तो बड़ा अच्छा है। इस तरह की आशा मैं मंत्री जी से रखता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): Mr. Deputy-Speaker, there are two Bills before us to consider, namely, the Cine-workers Welfare Cess Bill and the Cine-workers Welfare Fund Bill. This is a good measure. For the first time, the film artistes who are indigent circumstances have been given some protection, even though it has got its own limitation. But I would like to emphasise one point on the overall performance of the industry as well as on the functioning of a large number of workers attached to the established studios and other sectors of industry. They are really having no protection under any statute. I take this opportunity to impress upon the Minister that in this particular case, the film industry should be declared as an industry for all purposes so that the workers may have all protections under the existing legislations.

Let me come to the relevant clause 3 of the Cess Bill on which I have got strong objection regarding the excise duty, i.e., Rs. 1000/- imposed on feature films. All feature films are not made with same investments. There are feature films made with Rs. 10 crores, there are feature films made with a few lakhs of rupees and there are feature films made with lesser amounts. But you have fixed Rs. 1000/- for each feature film. That would not be sufficient to meet the welfare measures in the country. There should be some linkage of the actual production with investment in this particular field. That is my submission. According to your estimate, you intend to collect Rs. 7.5 lakhs. I do not know whether it will be sufficient for 1.5 lakh workers who are in a very bad situation and who have no protection. So, that should be linked with the actual investment in each film.

I am also surprised to find clause 6. You are giving exemptions for certain films. I have never seen such exemptions. You take any Bill regarding bidi or cigarette or any

other Bill. There is no such exemption for the sake of welfare measures. Why should clause 6 be inserted here for giving exemption to certain films? That is my second objection regarding this Bill.

Coming to the other points, one is that it should not be put into the Consolidated Fund because it is not going to benefit the workers. You should have a separate amount to be pooled together and put it in a separate account. Then only it will have sufficient impact of the welfare of workers.

I am very much surprised to see the provision regarding the Advisory Committees here. I do not know how many advisory committees are going to be proposed. Is it on the regional basis or on state-wise basis? And apart from all that, you have got the Central Advisory Committee. So, I have got my own anxiety and apprehension that whatever amount you collect may be eaten away by the Advisory Committees and their Members. The poor workers will not get anything out of this. So, please abolish the advisory committee and have some centralised machinery to screen it properly, in a proper way.

The last point which I would like to make is, it has not been clearly defined in clause 4 of the Welfare Fund Bill as to what are the welfare measures. What are the welfare measures they are going to provide to artists? I want some clarification on that The vagueness should not be there. What welfare measures are going to be devised by the advisory committees? I do not know.

With all these things I once again impress upon you that clause 3 should be amended. The important point that should be taken into consideration is that investment in production should have a linkage with the excise duty which you are going to collect.

The last point is regarding clause 2 where it is stated that a cine worker who is entitled to this benefit should have at least worked in five feature films. For that I have no objection. But regarding the other clause, the remuneration which you have fixed is not at all sufficient. Even in respect of a casual worker who works in this industry, the remuneration which you have fixed, that is, Rs. 1000/- per month, is not sufficient and so it should be enhanced to Rs. 2000/-. For others the amount which you have fixed at the rate of Rs. 5000/- should be enhanced to Rs. 10,000/-. That is my suggestion.

I think you will kindly consider all these things for the purpose of welfare measures.

I welcome this Bill and I thank you for giving me this opportunity.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE) : I must first of all thank the Hon. Members who have participated in the discussion on these two Bills. By and large this measure has been welcomed by the Member on both sides. There have been certain very valuable suggestions made by the Hon. Members. Some of them I am accepting and I am moving myself an amendment incorporating that advice and suggestion made by the Members. Some, I will explain, will not be possible to do at least at this stage.

One thing for which we may really feel sorry was when the very first speaker Shri Ajit Bag was speaking, he said that this was a good measure, but he made allegations of *mala fides* of the Central Govern-

ment as against the State Government. I really could not understand how this Bill is coming against the interests of the State Government in any manner whatsoever? He made trenchant criticism of the Central Government being authoritarian and this is one more example of the Central Government to such a thing. I could not understand him. He said that this is a State subject—exhibition, cinematograph, cinema exhibition.

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North-East) : No, he said, it is a Central subject.

आचार्य भगवान देव : जो बोले हैं वह बोलें तो ठीक है, आप क्यों बोल रहे हैं ?

SHRI VASANT SATHE : You do not even know this. I have got his speech here. Were you there at that time ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has got his speech, Mr. Maitra. If that Hon. Member is here he can object. Why are you objecting? Do not object.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Probably he spoke like that.

SHRI VASANT SATHE : The best thing would have been that Shri Bag could be there. His contention was that because this fell under the State list, Centre has no right to legislate on a matter which is under the State list. Now it is well known that as far as cinema exhibition is concerned, it is a State subject. That is why entertainment tax is a State subject or all exhibition of cinemas, but production of cinema and certification is Central subject. Welfare of workers is in the concurrent list and both can do welfare measures. Actually, there is nothing to prevent the State Government from bringing similar legislation for the welfare.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Or a better legislation.

SHRI VASANT SATHE : For the welfare of not only cinema workers but cinema theatre employees which do not come under our purview. This they should actually do to emulate this Bill because States have substantial revenue by way of entertainment tax. West Bengal Government earns more than Rs. 23 crores per annum on entertainment tax alone for exhibition of cinema. Why does the State Government not spend even a small percentage for the benefit of the employees working in cine theatres whose conditions are worse....

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jhadavpur) : You know that we have revived the studies only for the sake of workers and artistes........

SHRI VASANT SATHE : I know it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : And you have been supporting.

SHRI VASANT SATHE : Yes, I have been supporting. We have been giving money for that also from the National Films Development Corporation. As far as West Bengal Government is concerned, to any measure for the welfare of cine workers, we are giving the fullest co-operation from the Centre...

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Why don't you clear that Bill ?

SHRI VASANT SATHE : That Bill has nothing to do with this. It is pending somewhere else. It is not with me. I had cleared it. If it comes in the way of the Constitution what can I do ? (*Interruptions*) I would be required to amend the Constitution. That also I suggested, but the State Government of West Bengal is not accepting, I said, "At least agree to it so that I can have control over distribution in the

country". The West Bengal films cannot be shown anywhere else. This is a pity. I suggested that exhibition be brought at least under the Concurrent List. Even there, I gave an assurance that this would not affect their entertainment tax. But the West Bengal Government is not accepting that. Now what can I do? In everything you see ghost. That is the trouble. The West Bengal Gevernment and particularly our Marxist Party friends see ghosts even in a good thing, just as Mr. Ajit Bag saw ghost even in an innocuous and good measure like this. That is why I say, 'Please do not look even a good thing with coloured and jaundiced eyes'. That is what I request.

There was another point that was raised and that was, that an amount of Rs. 1,000, as collection, is too less. This is just a beginning. Let us at least make a beginning with this much. This is not the end of the matter. As we go ahead, we will see whether there are other ways like, as an Hon. Member suggested, linking it with investment or any other way; we will find out.

There was a suggestion from Mr. Daga and many other Hon. Members about the clause which says that should be required to give notice for collecting Rs. 1,000. Once he gets a certificate and goes away—Mr. Chatterjee knows—if I have to pursue the matter for Rs 1,000, that will require two years and I may spend more on collecting than the amount itself or than even on the administrative set-up. Therefore, I have accepted this suggestion. Now I am bringing an amendment whereby he will have to deposit this amount along with his application for certification. If he does not get the certification, I will return the amount together with interest. What more can be done ?

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY (Narasaraopet) : What is the amount that you expect to get out of this ?

SHRI VASANT SATHE : Rs. 7.5 lakhs—not much. This is not the only money that will be there. There would be loans, there would be grants, there would also be donations. So, I am hopeful that this amount would exceed at least Rs. 25 to 30 lakhs. This is only a beginning, as I said.

There was a misapprehension that this is going to apply to all the artistes. Shrimati Pramila said that even the rich people would be wiser, even the artistes who were not in indigent circumstances might get the benefit. They will not get the benefit. This is exclusively meant for those who are at the lowest rung—technicians, and extras that she talked of, those who do not earn even Rs. 1000 per film or a lump sum of Rs. 5,000 in five films. If such persons like technicians, extras, casual workers etc. As they are realy in the indigent circumstances, then we want to make a beginning to help them. So, I entirely agree with the other suggestions made by the Hon. Members. There are employees in other areas who also can be covered. May I say that I am going to introduce in this very session a comprehensive Bill on the Conditions of Service of Cine Employees. Fortunately this is cleared by the Law Ministry—drafting part of this. This I shall introduce in this session. There you can give me advice on the larger issues of the welfare of the employees.

This is a limited measure for the Welfare Fund for the indigent employees. All the good suggestions that you have made will be borne in mind by us. As far as the advisory committtee is concerned, there is going to be a Central Advisory Committee; for the time being, we have taken the enabling powers

throughout the country. There are more employees in the Southern region than in the Northern region; there are more employees in the Southern region, in the studies. Therefore, having one Central Advisory Committee may not be enough. After all, we deal with a particular person who is in indegent circumstance. What type of help will be the best for him is the point. The Fund will be operated by the ministry itself and not by anybody else. I must have the advice of competent persons from the field. That is why this provision is there to have men from the field, that is, those who are actually in this industry. That is the object of this Bill. Suppose someone is in need of some medical aid. It is no use giving the scholarship to his child. Do you understand what he needs? He needs medical aid. Like that, the Advisory Body will be able to see in what best manner we could help.

This is the objective. All the good suggestions which have been made are taken note of. As we go on with the experience of the Bill, we will also find out—this is for the first time that we are doing this—as to how we can cover all the other fields. Prof. Ranga and others pointed out about the artistes in the rural areas doing Ramayana, doing Navtangi, etc. in Maharashtra and other places. They wanted that they should also be covered. For radio, I am told, we have got a fund already known as 'non-lapsable fund'. A provision has now been made for funds to provide for Radio and T.V. artistes who may be in the indigent situations. That has already been approved and that will be done.

So, as far as the rural employees are concerned, it is a very big area, I would consider in what manner I can bring a measure which will cover them also. I would like to say again that this is for the State Governments. You earn more than Rs. 25 crores a year. Why can't one crore of rupees be set apart for the welfare of the employees in both the rural areas as well as in other areas for this ? I may tell you that you will be going a yeoman service. I request through this House and through the Members, the State Governments to please utilise a part of this fund. You can persuade your States to utilise even a part of the entertainment tax which they are earning from the films for the welfare of the workers.

With these words, I once again thank the Hon. Members for their kind co-operation.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let me first put the motion in respect of the Bill on Cine-Workers Welfare Cess Bill to the vote and complete all stage.

The question is :

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on feature films for the financing of activities to promote the welfare of certain cine-workers and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the House will take up Clause by Clause consideration of the Bill. On Clause 2 there is Government amendment No. 8.

Clause 2—(*Definitions*)

Amendment made :

"Page 1,—

after line 17, *insert*—

(d) "producer" in relation to a feature film means :

(i) the producer of such film; or

(ii) where the application for a certificate in respect of such film under section 4 of the Cinematograph Act, 1952, is made by any other person, such other person." (8)

37 of 1952

(*Shri Basant Sathe*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2:—*as amended, was added to the Bill.*

Clause 3 :—*(Levy and collection of cess on feature films)*

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : Sir, I beg to move :*

"Page 2, lines 1 and 2,

omit "With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint," (1)

"Page 2, lines 4 and 5,

for "at the rate of one thousand rupees on every feature film certified"

substitute

"at the rate of two thousand rupees on every feature film before the grant of certificate" (2)

*Moved with the recommendation of the President.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : I beg to move :*

"Page 2, line 4,

for "one" *substitute* "five" (5)

SHRI MOOL CHAND DAGA : Sir, Clause 1 says :

"It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette....."

Again it repeats the same thing in Clause 3. So, my amendment seeks to omit these words :

"With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint,"

What is the use of this repetition ? My second amendment is to the effect that instead of one thousand rupees it should be two thousand rupees. There are 3.5 lakh workers and with this meagre amount we will not be able to achieve the purpose. Out of this amount money will be spent on advisory committee, etc. So, I have suggested this amendment.

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, मेरा संशोधन बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। अभी कहा गया है कि इस बिल के अनुसार आप प्रत्येक कथा फिल्म पर 1 हजार रुपया सेस वसूल करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से— कहीं हम भिक्षा तो नहीं मांग रहे हैं ? आप कलाकारों की सहायता करना चाहते हैं, मैं एक फिल्म से 1 हजार रुपया मांगना मुनासिब नहीं समझता, जबकि एक-एक फिल्म पर लाखों रुपये, बल्कि करोड़ों भी हो

*Moved with the recommendation of the President.

सकते हैं, खर्च होते हैं और इसी तरह से वे उस फिल्म से करोड़ों रुपये कमाते हैं।

मेरा संशोधन यह है कि यदि आप सचमुच में कलाकारों की मदद करना चाहते हैं तो 1 हजार के बजाय 5 हजार कीजिये। मेरी दृष्टि में तो यह भी कम है, इससे भी ज्यादा होना चाहिये, लेकिन कम से कम इतना मान लीजिये। इससे यह लाभ होगा कि पैसा आपके पास कुछ ज्यादा आयेगा जिससे आप लोगों की ज्यादा मदद करने की स्थिति में हो जायेंगे। इसलिये आप इस संशोधन को जरूर स्वीकार कीजिये। वे गरीब नहीं हैं— गरीब से तो आप ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन अमीरों से एक हजार रुपए का भिक्षाटन कर रहे हैं। साठे साहब आप सरकार चला रहे हैं एक हजार के बजाए 5 हजार इसको कीजिए।

श्री वसन्त साठे : उपाध्यक्ष महोदय, डागा जी और शास्त्रीजी ने जो कहा, उनकी भावना को मैं भी समझ रहा हूँ। अगर इस में करोड़ों रुपया आता है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अभी जरा—इन्दताए इश्क है—आगे-आगे देखिए होता है क्या।

Amendment made :

Page 2, lines 5 and 6,

omit "certified for public exhibition under section 5A of the Cinematograph Act' 1952" (11)
37 of 1952

(*Shri Vasant Sathe*)

MR. DEPUTY SPEAKER : Now I will put amendments Nos. 1, 2 and 5 to the vote of the House.

Amendments Nos. 1, 2 and 5 were put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now the question is :

"That Clause 3, as amended stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4

(*Payment of duty of excise.*)

SHRI MOOL CHAND DAGA : I beg to move : *

Page 2, lines 12 and 13,

omit "from the date of notice of demand issued by that Government for such payment"

Sir, the procedure is very cumbersome and he has admitted it. That is why I have brought in this Amendment.

SHRI VASANT SATHE : I do not want to move my Amendment No. 9.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right. Amendment No. 9 not moved. Mr. Daga, have you anything more to say?

SHRI MOOL CHAND DAGA : As soon as they get the amount, they should deposit the amount. There is no question of any recovery procedure and all that. He has accepted the principle. I think he has already admitted this.

SHRI VASANT SATHE : I have already adopted what he says in the other amendments. So, I request him to withdraw his amendment.

SHRI MOOL CHAND DAGA : That is why I said, he has accepted the principle of my amendment.

*Moved with the recommendations of the President.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now we take up Government Amendment Nos. 12 and 13.

Amendments made :

Page 2, line 10, —

for "4." *substitute* "4. (1)" (12)

Page 2, —

for lines 12 and 13, *substitute* —

"on or before the date on which he makes an application for a certificate in respect of such film under section 4 of the Cinema-
37 of 1952 tograph Act, 1952 :

Provided that the producer of such film may apply to the Central Government for the refund of the duty paid by him in respect of such film on the ground :—

(a) that an order refusing to grant any certificate in respect of such film has been made under section 4, read with section 5A, of the Cinemato-
37 of 1952 graph Act, 1952 ; and

(b) that he does not intend to appeal against, or seek revision of, such order, or, as the case may be, that the said order has been confirmed on appeal or revision under the said Act :

Provided further that in case any certificate is granted under the said Act in respect of any film after the refund under the preceding proviso of the duty paid in respect thereof, the producer shall be liable to repay, within a period of seven days from the date of grant of such certificate to the Central Government the duty so refunded.

(2) Simple interest shall be payable at the rate of twelve per cent per annum,—

(a) by the Central Government on the amount of duty in relation to any film refunded by it under the first proviso to sub-section (1), from the date of the payment of such duty till the date of such refund ;

(b) by the producer of a film on any amount of duty refunded to him under the first proviso to sub-section (1) and repaid by him to the Central Government under the second proviso to that sub-section, from the date of such refund to the date of such repayment." (13)

(*Shri Vasant Sathe*)

MR DEPUTY-SPEAKER: Mr. Daga, I think you are withdrawing Amendment No. 3.

SHRI MOOL CHAND DAGA: He has already accepted the principle. I seek leave of the House to withdraw my amendment No. 3.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Has the Hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

Amendment No. 3 was, by leave, withdrawn

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the question is :

"That Clause 4, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5 :—(*Crediting proceeds of duty to Consolidated Fund of India.*)

SHRI MOOL CHAND DAGA : I beg to move* :

Page 2, line 15,—

for "Consolidated Fund of India"

substitute

"The Cine Workers Welfare Fund" (4)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I beg to move* :

Page 2, line 15, —

for "Consolidated Fund of India" *substitute*

"Cine-Workers Welfare Fund formed under section 3 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981." (6)

*Moved with the recommendation of the President.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Daga, you can speak about your amendment.

SHRI MOOL CHAND DAGA : The amount should go to the Cine-workers Welfare Fund. Why this 'Consolidated Fund of India' is brought in here ? Otherwise he will again have to go to the Government and withdraw the money from the Consolidated Fund of India. Therefore, I say, this should be 'Cine-Workers Welfare Fund', and it should not go to 'Consolidated Fund of India.' That is the purpose of my amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Ramavatar Shastri. Please make a short speech.

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें धारा 5 में कहा गया है कि जो भी पैसा जमा होगा वह "संचित-निधि" में जमा किया जाएगा। मैं इसको गलत मानता हूं और मेरा संशोधन है कि "सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981" की धारा 3 के अधीन स्थापित "सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि" में जमा किया जाए। क्यों मैं ऐसा कहता हूं ? निधि की कृपा पर आप क्यों रखना चाहते हैं। आप तो रहिए सो रहिए, लेकिन बेचारे गरीब कलाकारों को उनकी कृपा पर क्यों रखना चाहते हैं ? एक स्वतंत्र निधि उनके फायदे के लिए बनाने में जिस का नाम मैंने और डागा जी ने भी सुझाया है, आपको क्या आपत्ति है, क्या कठिनाई है यह मेरी समझ में नहीं आया है। अगर कोई कठिनाई हो तो बताएं। संचित निधि से अगर कुछ

[श्री रामावतार शास्त्री]

ज्यादा कलाकारों को मिलने की उम्मीद हो तो वह भी बताए। तब मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। मेरा निवेदन है कि इस पैसे को आप संचित निधि में न रखें और एक विशेष निधि की स्थापना करें और उसी में इसको रखें।

SHRI VASANT SATHE : Sir, the simple reason why we have put it in the Consolidated Fund is that it forms the part of the nature of an excise duty. That is why I cannot put it in a different fund. I have to put it in the Consolidated Fund where all excise duty goes. And once the Bill is passed, in the Budget itself that provision is made and this will be separately shown and hopefully, as I said, not only this much, but I will get something more from the Finance Minister towards the Fund. Therefore, I am not scared at all in its going to the Consolidated Fund. That is the reason why it should go to the Consolidated Fund.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Sir, I seek leave of the House to withdraw my amendment.

Amendment No. 4 was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Ram Avtar Shastri is pressing his amendment. I will put his amendment to the vote of the House.

Amendment No. 6 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, I will put Clause 5 to the vote of the House.

The question is :

"that Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7—*Penalty for non-payment of duty of excise within the prescribed period.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Clause 7, Amendment No. 7.

SHRI RAM AVTAR SHASTRI : Sir, I beg to move* :

Page 2, line 27—

for "fifty"

substitute "three hundred". (7)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we take Government Amendment No. 14.

SHRI VASANT SATHE : I beg to move :

Page 2, lines 23 and 24,—

for "is not paid to that Government within the period specified thereunder"

substitute—

"(including any duty of excise which has been refunded but which is required to be repaid to that Government under the second proviso to sub-section (1) of that section) is not paid to that Government before the date, or, as the case may be, within the period specified therein". (14)

*Moved with the recommendation of the President.

श्री रामावतार शास्त्री : इस विधेयक की धारा 7 में प्रत्येक फिल्म निर्माता को उत्पाद शुल्क देना होगा और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है और यह शुल्क उस समय के भीतर अदा कर दिया जाना चाहिये और अगर वह समय पर अदा नहीं करता है तो उसको इसके अधीन जुर्माना देने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि जितने महीने यह शुल्क अदा नहीं किया जाएगा उतने महीने के लिए प्रत्येक महीने का पचास रुपया उसको देना होगा। निर्माता बहुत बड़े लोग होते हैं, मालिक लोग होते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। उनसे पचास रुपया प्रति महीना लेने की बात समझ में नहीं आई है। यह सजा पचास रुपये की जगह पर तीन सौ रुपये महीना होना चाहिये। उनसे प्रति माह तीन सौ रुपया लिया जाना चाहिये। 300 रु० उनसे लीजिये। नहीं तो 50 रु० का कोई मतलब नहीं होता है। वह उत्पाद शुल्क समय पर नहीं देंगे। इसलिये अगर समय पर वसूल करना चाहते हैं तो थोड़ी सख्ती करनी होगी निर्माताओं पर ताकि वह समय पर उत्पाद शुल्क दे सकें। इसलिये मेरा संशोधन है कि 50 की जगह पर 300 रु० कर दिया जाय।

16 hrs.

MR. DEPUTY SPEAKER : At 4 o'clock, we have got to take up the special discussion on a Motion. I would very much like that this Bill is passed, because it is pending for the last three days. We will complete it. It will not take much time. Now Shri Sathe.

SHRI VASANT SATHE : I don't think this needs even a reply. After all, I have said that we are making a beginning.

50 रु० से 500 रु० करो उससे काम नहीं चलेगा। पेनाल्टी बढ़ाने की नौबत नहीं आयेगी।

MR. DEPUTY SPEAKER : I now take up Government amendment No. 14 first.

The question is :

Page 2, lines 23 and 24,—

for "is not paid to that Government within the period specified thereunder"

substitute—

"(including any duty of excise which has been refunded but which is required to be repaid to that Government under the second proviso to sub section (1) of that section) is not paid to that Government before the date, or, as the case may be, within the period specified therein." (14)

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the amendment of Mr. Ramavatar Shastri.

The question is :

Page 2, line 27, —

for "fifty" *substitute* "three hundred" (7)

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : In clauses 8 to 10, there are no amendments. The question is:

"That clauses 8 to 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 to 10 were added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That Clause I, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now the Minister.

SHRI VASANT SATHE : I beg to move.

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : We will take up the other Bill—the Cine-Workers Welfare Fund Bill. It will take only 2 or 3 minutes.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : No. I have got six amendments. I will speak on all of them.

SHRI VASANT SATHE : Will the opposition not cooperate ? Here is a welfare Bill. Just 5 or 10 minutes more, and we can adopt that.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : No. It cannot be.

MR. DEPUTY SPEAKER : Are you not considering Government's request.

Their request is that it is only a welfare measure.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : No.

16.04 hrs.

Motion *re* current price situation

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN) : I beg to move :

"That this House do consider the current price situation and the steps taken by the Government to tackle it."

I will make a brief statement and then I will reply in detail to the various points raised by the Hon. member. The price situation in the country does cause a great deal of concern to the Government. Whatever I say in the course of this debate defending the action of the Government or putting in a little strong language in defence of the Government should not be misunderstood as in any way detracting from the concern which this Government has for the very disturbing feature, namely, the price situation in the country.